

सेक्टर 14 की डॉक्टर बेटी अपने दम पर वायुसेना में बनी फ्लाइट लेफ्टनेंट



फ्रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 14 की रहने वाली जिगिशा लखनपाल एमबीबीएस की पढाई पूरी करके भारतीय वायुसेना में बतौर डॉक्टर फ्लाइट लेफ्टनेंट के पद पर भर्ती हो गयी। दिनांक 22 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिंडन वायुसेना स्टेशन पर कमीशन रेंक प्रदान किया गया।

जिगिशा पहली जमात से 12 वीं तक सेक्टर 15 स्थित एपीजे स्कूल में पढ़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2011 में 95 प्रतिशत अंकों से 12 वीं की परीक्षा पास की थी। पढाई के अलावा जिगिशा अपने स्कूल की सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी रही है। पढाई में इतने अच्छे अंक प्राप्त कर लेने के बावजूद सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में उन्हें दाखिला नहीं मिला तो उन्हें पूछा कि एक निजी मेडिकल कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ में दाखिला लेना पड़ा। अपनी विलक्षण प्रतिभा के दम पर उन्होंने वहां भी हर वर्ष अच्छे परिणाम दिये और निश्चित समय में परीक्षा पास करके 2016 में लौट आई। दिल्ली के विलिंगडन (राम मनोहर लोहिया) अस्पताल से इन्ऱर्नशीप पूरी करने के बाद कुछ माह स्थानीय इंएसआईसी मेडिकल कॉलेज में बतौर जेआर काम किया। अब उनका चयन भारतीय वायुसेना में हो गया।

इस सारी कहानी में गैरतलब बात यह है कि 'बेटी बच्चाओं बेटी पढ़ाओ' का खोखला नारा देने वाली भारतीय जुमलेबाज पार्टी की सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं। भूमिका तो इनसे पहले वाली सरकारों की भी कोई नहीं रही लेकिन वे इतने बड़े जुमलेबाज तो नहीं ही थे।

जिगिशा की कामयाबी के पीछे बड़ी भूमिका उनके माता-पिता की रही है जिन्होंने एपीजे जैसे महंगे स्कूल में उसे पढ़ाया। यदि खर्च बचाने के चक्कर में बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाया होता तो वह कभी इतने अच्छे अंकों से 12 वीं पास न कर पाती। उसके बाद निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का मतलब कम से कम 2 करोड़ का खर्च उन्होंने उठाया। तथाकथित भारतीय संस्कृति, जिसमें बेटी को पराया धन समझा जाता है, कोई मां-बाप आसानी से बेटी पर खर्च नहीं करता। लेकिन जिगिशा के माता-पिता ने उसे बेटे की तरह ही पाला-पोसा है। इसके लिये जिगिशा के साथ-साथ वे भी बधाई के पात्र हैं।

दूसरा व्यवस्थागत गंभीर सवाल यह उठता है कि डॉक्टर बनने के लिये, 12 वीं तक की पढाई का खर्च न भी जोड़ें तो मेडिकल की पढाई पर ही जब कोई 2 करोड़ खर्च करेगा तो क्या एक लाख मासिक वेतन उसे सन्तुष्ट कर पायेगा? यही वह मुख्य कारण है जिसके चलते डॉक्टर भटक कर इधर-उधर मुह मारने लगते हैं। डॉक्टरों को जनहित, देशहित, समाजहित में सेवा का उपदेश देने से पहले समाज एवं सरकार को पर्याप्त मात्रा में मेडिकल कॉलेज खोल कर उन्हें मुफ्त मेडिकल शिक्षा देने का जिम्मा लेना चाहिये।

सरकारी जमीन पर किराया वसूल रहे हैं निगमकर्मी व दुकानदार

करनाल : त्योहारों के मौसम में नगरनिगम की लापरवाही और पुलिस की सुस्ती के चलते दुकानदार अपने आगे सरकारी जमीन से मोटा किराया वसूल रहे हैं। इससे शहर में अतिक्रमण बढ़ रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्य बाजारों से गुजरना मुश्किल हो गया है। खास कर कर्ण गेट बाजार के हालात तो काफी खराब हैं। हालत यह है दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे नगर निगम की जगह ही फड़ी लगाने के लिये किराये पर दे दी है। यदि यह कहा जाये कि दुकानदार आम के आम गुरुत्वियों के दाम वसूल रहे हैं तो यह गलत न होगा।

दुकानदार तो दुकानदार नगर निगम के अधिकारी व ट्रेफिक पुलिस भी कम नहीं हैं। जहां जिसका दांव लगता है रेहड़ी फड़ी बालों से नजराना वसूल रहे हैं। पुरानी सब्जी मण्डी चौक पर पुलिस बूथ बना हुआ है, ठीक पुलिस बूथ के सामने सड़क के दूसरी ओर एक व्यक्ति फड़ी लगा कर जगह घेरे हुये है। रात को जाते समय पुलिस बूथ पर अपना फड़ी का सामान रख कर चला जाता है। और सुबह पुलिस कर्मचारी उसका समान निकाल कर फड़ी लगाने को उसे दे देते हैं। सिलसिला वर्षों से जारी है। हैरानी की बात तो ये है कि उसी जगह सीसी टीवी कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन उच्चाधिकारियों ने आज तक इसे संज्ञान में नहीं लिया। जाहिर है यह सब बिना मंथली नजराना के नहीं हो सकता।

दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी भी पीछे नहीं हैं। दुकानदार तो अपनी दुकान के आगे फड़ी लगाने के पैसे तो ले ही रहे हैं परन्तु उन फड़ी बालों से नगर निगम के अधिकारियों ने भी मंथली बांध ली है। कभी कभार खाना पूर्ति के लिये छोटा मोटा चालान कर देते हैं।

कुछ दुकानदारों का कहना है हमारी दुकानों के सामने बैंक होने के कारण लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके बैंक चले जाते हैं और घटों नहीं आते। निगम के अधिकारियों शिकायत करते हैं तो वह कोई कारवाई नहीं करते। उल्टा कहते हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं।

इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। शहर के मुख्य बाजार कर्णगेट से लेकर घण्टाघर चौक तक दुकानों के आगे लगी फड़ियों से रास्ता जाप हो रहा है, साथ ही सड़क पर खड़े वाहनों के कारण भी निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि कभी कभार नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला कर दुकानों के आगे लगी फड़ियों को हटा देते हैं परन्तु फिर यह फड़ियां लग जाती हैं। हालांकि लोग इसे नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत भी बताते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुरानी सब्जीमण्डी व हांसी रोड पर भी अतिक्रमण के चलते यातायात अवरुद्ध रहता है। उधर नगर निगम के अधिकारी मानते हैं कि दुकानदारों ने आगे की सरकारी जगह तक कवर कर रखा है। दुकानदार नगर निगम की जगह को भी किराये पर देकर किराया वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है परन्तु फिर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। परन्तु भूले से भी वे अपनी मंथली का जिकर नहीं करते।

शिक्षा विभाग: सरकारी ग्रांट हड्डपने के बाद अब निजी धन पर भी नज़र

फ्रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 14 की रहने वाली जिगिशा लखनपाल एमबीबीएस की पढाई पूरी करके भारतीय वायुसेना में बतौर डॉक्टर फ्लाइट लेफ्टनेंट के पद पर भर्ती हो गयी। दिनांक 22 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिंडन वायुसेना स्टेशन पर कमीशन रेंक प्रदान किया गया।

जिगिशा पहली जमात से 12 वीं तक सेक्टर 15 स्थित एपीजे स्कूल में पढ़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2011 में 95 प्रतिशत अंकों से 12 वीं की परीक्षा पास की थी। पढाई के अलावा जिगिशा अपने स्कूल की सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी रही है। पढाई में इतने अच्छे अंक प्राप्त कर लेने के बावजूद सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में उन्हें दाखिला नहीं मिला तो उन्हें पूछा कि एक निजी मेडिकल कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ में दाखिला लेना पड़ा। अपनी विलक्षण प्रतिभा के दम पर उन्होंने वहां भी हर वर्ष अच्छे परिणाम दिये और निश्चित समय में परीक्षा पास करके 2016 में लौट आई। दिल्ली के विलिंगडन (राम मनोहर लोहिया) अस्पताल से इन्ऱर्नशीप पूरी करने के बाद कुछ माह स्थानीय इंएसआईसी मेडिकल कॉलेज में बतौर जेआर काम किया। अब उनका चयन भारतीय वायुसेना में हो गया।

इस सारी कहानी में गैरतलब बात यह है कि 'बेटी बच्चाओं बेटी पढ़ाओ' का खोखला नारा देने वाली भारतीय जुमलेबाज पार्टी की सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं। भूमिका तो इनसे पहले वाली सरकारों की भी कोई नहीं रही लेकिन वे इतने बड़े जुमलेबाज तो नहीं ही थे।

'मजदूर मोर्चा' ने अपनी जांच में पाया कि अप्रैल 2015 में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने गरीब एवं प्रतिभावान बच्चों की सहायतार्थ कुछ शिक्षकों को अपने स्कूल के जरूरतमंद छात्रों के लिये भी ऐसा ही एक निजी फंड बना कर रखा था जिससे गरीब बच्चों को काफ़ी सहायता मिलती थी। पदान्त देने के बाद उन्होंने अपनी योजना को विस्तार देते हुये खंड स्तर पर लागू करने का विचार बनाया था। उसी दौरान मंजीत सिंह नामक एक उप जिला शिक्षा अधिकारी ने रितु चौधरी पर दबाव बनाया कि वे उसके ड्राइवर की पाली को किसी स्कूल में फ़र्जी तौर पर मिड-डे-मील बनाने की नौकरी दे दें। न मानने पर मंजीत ने उनके खिलाफ़ एक नियन्त्रित रचने शुरू कर दिये। दूसरी ओर मंत्री

कृष्णपाल गूजर ने कुछ शिक्षकों को बतौर कार्यकर्ता पाल रखा था जो स्कूल में आते ही नहीं थे। रितु द्वारा की गयी सख्ती एवं मंत्री गूजर की चापलूसी न करने पर वह भी सख्त नाराज़ था। परिणामस्वरूप रितु का यहां से तबादला करा दिया। दो-चार महीने पहले खोला गया 5 लाख का फ़ंड ज्यों का त्यों धरे का धरा रह गया। चूंकि यह फ़ंड रितु ने अपनी निजी क्षमता एवं सामाजिक सहयोग से खोला था जिसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा था अब अछूत पड़ा है।

यहां का चार्ज छोड़ने से पहले रितु ने अपने निदेशालय को पत्र लिख कर सूचित कर दिया था कि उनके द्वारा बनाये फ़ंड को निदेशालय सम्भाले तथा तय कर देकि कौन और कैसे इसका प्रयोग करेगा। लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। आयोग भी नहीं क्योंकि यह एक निजी फ़ंड है, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। लिहाजा इसका प्रबन्धन एवं इस्तेमाल केवल वह करमेंटी कर सकती है जिसने उसे बनाया है। लेकिन इस सब से मौजूदा फ़ंड शिक्षा अधिकारी मुनीष चौधरी को भारी परेशानी